**12.00 Hrs.**

OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Official Languages Act, 1963.

Some Hon. Members : *rose—*

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : Sir, I rise to a point of order.

MR. SPEAKER : Order, order. All hon. Members may resume their seats. I will call them one by one. I will give a chance to all of them. Dr. Govind Das—

**डा० गोविंद दास** (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, मैं चह्वाण साहब का बड़ा आदर करता हूं और मैं उसी दल का हूं जिस दल के श्री चह्वाण जी हैं । उस दल से मैं केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में गत 44 वर्षों से रहा । परन्तु मुझ बहुत खेद है कि जो प्रस्ताव श्री चह्वाण जी ने यहां उपस्थित किया है उस का मैं विरोध करता हूं । यह विधेयक मेरे मतानुसार संविधान के प्रतिकूल है । संविधान में यह बात स्पष्ट कही गई है कि सन् 1965 के 26 जनवरी के बाद हिन्दी इस देश की राजभाषा हो जाती है और अंग्रेजी का उपयोग केवल उन बातों के लिए किया जा सकता है कि जिन के लिए वह आवश्यक मानी जाय । जो विधेयक श्री चह्वाण जी ने उपस्थित किया हैं उस विधेयक में यह कहा गया है कि सारे विषयों के संबंध में अंग्रेजी का उपयोग किया जा सकेगा । मेरा यह निवेदन है कि संविधान के यह विधेयक विरुद्ध है । ठीक बात यह होती कि संविधान के संशोधन के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता । मुझे ऐसा लगता है कि सरकार शायद यह समझती है कि संविधान के संशोधन के लिए जितने मत उन को चाहिएं उतने मत उन के पास नहीं हैं । इसलिए एक परोक्ष रीति से संविधान में संशोधन किए बिना ऐंसी बातें इस विधेयक में कही गई हैं जो संविधान के प्रतिकूल हैं और संविधान के प्रतिकूल होते हुए भी इस विधेयक के कारण यह बातें की जायेंगी । इस के सिवाय मेरा यह निवेदन भी है कि भाषा के प्रश्न को यह विधेयक सुलझाता नहीं है, उलटे उलझाता है । यदि हमारे मद्रास के बन्धु या दूसरे अहिन्दी-भाषा भाषी राज्य यह चाहते हैं कि वह हिन्दी का इस्तेमाल न करें तो मैं उनको पूरी आजादी इस बात की देना चाहता हूं कि हिन्दी उन पर न लादी जाय । हिन्दी का वह कभी भी उपयोग न करें । हिन्दी कभी भी न सीखें । लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चहता हूं कि संविधान के विरुद्ध जो इस विधेयक में यह प्रयत्न किया गया है कि जो हिन्दी भाषी हैं उन पर भी अंग्रेजी लादी जाय यह बहुत अनुचित बात है । इस विधेयक का अर्थ यह होगा कि जो अपने अपने राज्यों में सब काम हिन्दी में करना चाहते हैं, हिन्दी चलाना चाहते हैं, उन के ऊपर भी अंग्रेजी लदी रहेगी, जो कि संविधान के प्रतिकल है । मैं यह चाहता था कि श्री चह्वाण जी इस विधेयक को उपस्थित करने के पहले हर दल के नेताओं को और हर राज्य के मुख्य मंत्रियों को यहां पर बुला कर एक गोलमेज परिषद् करते जिस में इस विषय पर पूरा विचार किया जाता और विचार करने के उपरांत इस प्रकार का विधेयक उपस्थित किया जाता या संविधान में संशोधन किया जाता । मैं अहिन्दी भाषी जो राज्य हैं उन के संतोष के लिए संविधान में भी परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं । इसका मैं विरोधी नहीं हूं । जो राज्य अपने यहां पर अंग्रेजी चलाना चाहते हैं, हिन्दी नहीं चलाना चाहते उन को पूरी आजादी होनी चाहिए । लेकिन संविधान के विरुद्ध इस प्रकार का विधेयक उपस्थित करना इसमें गैर-कानूनी समझता हूं और इसीलिए बड़े खेद के साथ मैं चह्वाण जी के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*Published in Gazette of India Extra Ordinary, Part II, Section 2, dated 27th November, 1967.

Some Hon. Members : *rose*—

MR. SPEAKER : I have before me five names—Shri Yashpal Singh, Shri Prakash Vir Shastri, Dr. Govind Das, Shri Madhu Limaye and Shri Kanwar Lal Gupta. That is the order in which notices have been received by office from them. After calling them, I will call others.

**श्री मधु लिमये** (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, आप माफ करेंगे, मुझे थोड़ा समय लगेगा। में आप का ध्यान नियम 72 की ओर दिलाना चाहता हूं।

SHRI MANOHARAN (Madras North): Considering the importance of the Bill, I hope you will give opportunities to other Members also.

MR. SPEAKER : I will give an opportunity to DMK after these five members have expressed their view. For the present they need only say how it is unconstitutional. Later on, they can oppose it.

**श्री मधु लिमयें** : यही मैं तो कह रहा हूं। मैं केवल विनती यह कर रहा हूं कि इस नियम के अन्दर यह कहा गया है कि :

"Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

इसलिए मैं ने आप का ध्यान इसकी ओर खींचा है।

यह जो विधेयक हमारे सामने आया है ऐसा लगता है कि संविधान की धारा 343 और उपधारा (3) के तहत आया है। आपकी जानकारी के लिए अध्यक्ष महोदय, और सदन की जानकारी के लिए मैं यह धाराएं पढ़ना चाहता हूं। धारा 343 (1) के तहत यह कहा गया है कि हिन्दी केन्द्र की आधिकारिक भाषा बन जायगी और उसकी लिखावट देवनागरी लिपि में होगी। आगे चल कर अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है 343 (2) के अन्दर :

"Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement :"

अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक है, वह इस उपधारा के तहत नहीं है क्योंकि इस उपधारा के तहत किसी भी विधेयक की आवश्यकता नहीं थी। संविधान में कहा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद 15 साल तक अगर सरकार चाहे तो अंग्रेजी का इस्तेमाल सभी कामों के लिए चालू रख सकती है जिन कामों के लिए 26 जनवरी 1950 के पहले इस्तेमाल हो रहा था। यह जो विधेयक आया है वह उपधारा (3) के तहत है जो इस प्रकार है :

"Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of—

(a) the English language, or

(b) the Devanagari form of numerals, for such purposes as may be specified in the law."

अध्यक्ष महोदय, अब मेरा पहला आक्षेप यह है कि इस विधेयक की जो भाषा है उसको आप देख लीजिए। इस विधेयक में कहा गया है पहले पृष्ठ का अंतिम वाक्य देखिये :

"for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before that day;"

इसकी परिभाषा और उपधारा (2) की परिभाषा एक है। मतलब, अध्यक्ष महोदय, 15 साल की अवधि में सभी कामों के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल संवैधानिक था। लेकिन 15 साल की अवधि खत्म होने के पश्चात् 1965 के बाद सभी कामों के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल वैध नहीं है, गैर कानूनी है। क्योंकि उपधारा 3 जोकि 15 साल के बाद अमल में आती है, 1965 के बाद।

[श्री मधु लिमये]

उस में जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है, वह अलग है—

"for all purposes of the Union"

नहीं है, उसमें कहा गया है—

"for such purposes as may be specified in the law"

मतलब जो कानून उपधारा 3 के तहत बनेगा, उस में कुछ विशिष्ट कामों का उल्लेख करना चाहिये, जिसके लिये अंग्रेजी का इस्तेमाल चल सकता है। लेकिन इन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, वे उपधारा 2 के शब्द हैं, उपधारा 3 के नहीं हैं। "for the purposes specified in this Act."

अगर ये शब्द होते तो इस विधेयक में उन को विशिष्ट कामों का उल्लेख करना पड़ता और अगर इस तरह का उल्लेख वह करते, तो मैं संवैधानिक और कानूनी आपत्ति नहीं उठाता। लेकिन चूंकि इन्होंने उपधारा 2 की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जो 15 साल की अवधि के लिये लागू थी, 15 साल के बाद नहीं, 15 सालों के बाद केवल विशिष्ट कामों के लिये अंग्रेजी चल सकती थी, इसलिये सब से पहले मेरा आक्षेप यह है कि यह संविधान की उपधारा 3, धारा 343 के खिलाफ है।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, धारा 343 की योजना आप देखिये। पांच साल के बाद एक कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिए और इस कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी क्या डाली गई है—344(2) में यह साफ लिखा है कि—

"It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to—

(a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;

(b) restrictions on the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union;"

असल में कमीशन इसलिए बना था और उस को यह सिफारिश करनी थी कि 15 साल की अवधि में किन कामों के लिये हिन्दी का इस्तेमाल किया जाय और किन कामों के लिये धीरे धीरे अंग्रेजी के ऊपर पाबन्दी लगाई जाय। 15 सालों के बाद सभी क्षेत्रों में हिन्दी आ जायगी, केवल विशिष्ट कामों के लिये अंग्रेजी का इस्तेमाल कानून के जरिए चालू रखा जा सकता है तो संविधान की सभी धाराओं की इसमें हत्या हो रही है—इस भाषा सम्बन्धी विधेयक में।

अध्यक्ष महोदय, एक और धारा की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं—वह धारा 351 है। हिन्दी भाषा कैसी है और उस के लिये इस सरकार को क्या करना चाहिये। इस के बारे में कहा गया है कि—

"It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages."

तो संविधान की यह पूरी योजना थी। मेरा इस सरकार पर आरोप है कि इस संविधान की एक एक धारा की उन्होंने हत्या की है। कहा जायगा कि पं० जवाहर लाल नेहरू का आश्वासन था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जवाहर लाल नेहरू मेरे नेता नहीं थे और उन्होंने जो कुछ भी आश्वा-

सन दिया है, उस से मुझ को बिलकुल मतलब नहीं है और में यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी भी नेता को आनेवाली पीढ़ीयों के ऊपर पाबन्दी लगाने या उन को बांधने का कोई अधिकार नहीं है—चाहे नेहरू हों या और कोई नेता हों। अध्यक्ष महोदय, आज इस कानून के द्वारा न केवल संविधान की हत्या की जा रही है, बल्कि राष्ट्रीय आजादी के आन्दोलन में जिन जिन मूल्यों और आदर्शों को हम ने प्रधानता दी, हमारे दिलों में स्थान दिया, उस को ये लोग खत्म करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज फिर में यह नारा सुन रहा हुं कि कुछ अवधि बढ़ाओ, 5 साल, 10 साल, उस के बाद हिन्दी आ जायगी। में कहता हूं कि 15 सालकी अवधि के बाद जो हुआ, उस को देखते हुए इस तरह की बात करना कि पांच साल और दे दो दस साल और दे दो, में समझता हूं कि यह बेईमानी नहीं तो आत्मवंचना और परवंचना जरूर है। इस लिये, अध्यक्ष महोदय, में यह कहना चाहता हूं कि इस समय अवधि की बात करना बिलकुल बेमतलब है और में अवधि की बात नहीं करना चाहता हूं। साथ ही साथ जो लोग यह कहते हैं कि कुछ समय दिया जाय, अन्ततोगत्वा हम हिन्दी को कबूल ही करने वाले हैं, केरल में, आन्ध्र में, मैसूर में और हिन्दुस्तान के जो हिन्दी भाषी इलाके हैं, वहां से भी ये आवाजें मैं सुनता हूं कि हिन्दी आ जायगी, कुछ और वक्त दिया जाय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस में भी हम अपने को धोखे में डाल रहे हैं। हिन्दी का ज्ञान दक्षिण में तेजी के साथ बढ़ रहा है—इस के बारे में दो रायें नहीं हो सकती हैं। लेकिन उस के लिये श्रेय में इन लोगों को नहीं देना चाहता हूं—हमारी फिल्मों ने, हमारे सिनेमा उद्योग ने हिन्दी के प्रचार के लिये जितना काम किया है, शायद ही....

MR. SPEAKER: You can go to that later on.

**श्री मधु लिमये** : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि हिन्दी का ज्ञान तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ दक्षिण में और दूसरे इलाकों में हिन्दी विरोधी भावना भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ रही है। इसलिये जो माननीय सदस्य समझते हैं कि हिन्दी का ज्ञान बढ़ेगा, तथा धीरे-धीरे सब लोग हिन्दी को स्वीकारेंगे—वह चीज, मैं समझता हूं कि नहीं होनेवाली है। इस लिये मेरा सुझाव है कि जैसे डी० एम० के० के लोग हैं, उन के साथ बातचीत कर के हो सकता है कि कोई नया रास्ता निकले। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अंग्रेजी पढ़े-लिखे मुट्ठी भर लोगों के स्वार्थों को कायम रखने के लिये, उन के स्वार्थों की रक्षा करने के लिये, जो अंग्रेजी का नारा दे रहे हैं, उनके साथ मुझे बिलकुल हमदर्दी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह कानून संविधान के प्रतिकूल है, अब में उस में न जाकर, यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हिन्दी चलाने में यह सरकार असमर्थ है, अहिन्दी भाषी इलाकों के लोग अगर हिन्दी को नहीं चलाना चाहते हैं—केन्द्रीय भाषा के रूप में, तो मेरा ख्याल है कि अब समय आ गया है कि संविधान की धाराओं के बारे में हम नये सिरे से सोचें। मैं इस बात का विरोधी हूं कि हमेशा हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहें, उस को देवता बनायें और किसी मन्दिर में उस को रख कर उस की पूजा करें, लेकिन उसका इस्तेमाल न करें। इस को मैं बेईमानी समझता हूं। इसलिये दूसरा रास्ता क्या हो सकता है—मेरी यह राय है कि यह सदन फैसला करे, राज्य सभा फैसला करे, में किसी भी राज्य पर हिन्दी लादना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हर एक राज्य की विधान सभा को यह स्वतन्त्रता होकि केन्द्रीय कामों के

[श्री मधु लिमये]

लिये, अन्तरप्रान्तीय कामों के लिये वह प्रस्ताव के जरिये इस की घोषणा करें कि वह अंग्रेजी को पसन्द करते हैं या हिन्दी को पसन्द करते हैं । मैं हर राज्य की विधान सभा पर यह बात छोड़ देना चाहता हूं । साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन राज्यों की विधान सभाओं ने हिन्दी के हक में प्रस्ताव पास किया है और मुझे उम्मीद है कि न केवल हिन्दी भाषी राज्य—जो पांच हैं—बल्कि अगर महाराष्ट्र में और गुजरात में थोड़ी भी अकल बाकी है, तो मैं यह चाहता हूं—मोरारजी भाई बैठे हैं, चह्वाण साहब बैठे हैं—अगर इन लोगों में थोड़ी भी समझदारी बाकी है, तो मुझे आशा है कि गुजरात विधान सभा और महाराष्ट्र विधान सभा और हो सकता है कि पंजाब की विधान सभा भी फैसला करेगी कि हम तत्काल हिन्दी को केन्द्रीय भाषा के रूप में और अन्तरप्रान्तीय व्यवहार के लिये स्वीकार करने को तैयार हैं तो ऐसे राज्यों पर अंग्रेजी न लादी जाय । फिर सवाल रह जायगा—दक्षिण के चार राज्यों का, बंगाल का, असम और उड़ीसा का । अध्यक्ष महोदय, उस के बारे में यह समझौता हो कि इन राज्यों के ऊपर हम हिन्दी को न लादें ।

लेकिन साथ-साथ मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि जो राज्य अंग्रेजी को नहीं चाहते हैं उन के ऊपर अंग्रेजी को लादा जाये । उत्तर प्रदेश में . . .

MR. SPEAKER: He should not go into the merits of the Bill now; that will be going outside the scope.

**श्री मधु लिमये** : मैं यह कह रहा हूं कि यह विधेयक संवैधानिक नहीं है । संवैधानिक क्या हो सकता है यह मैं बतला रहा हूं । यह समझौता हो कि किसी के ऊपर अंग्रेजी लादी न जाय, किसी के ऊपर हिन्दी लादी न जाये और केन्द्रीय दफ्तरों में जो हिन्दी को स्वीकार करने वाले राज्य हों, उन में हिन्दी में काम चलाया जाये । जो राज्य हिन्दी को स्वीकार करने के लिये तैयार न हों वह अंग्रेजी में काम करें । केन्द्रीय सचिवालय में दो विभाग बनें । एक हिन्दी के जरिये काम करे और दूसरा अंग्रेजी के जरिये काम करे । लेकिन किसी के ऊपर भी अंग्रेजी में अनुवाद करने की जबर्दस्ती न की जाये, क्योंकि किसी भी कर्मचारी या अफसर पर अगर जबर्दस्ती की जायेगी तो कौन ऐसा मूर्ख कर्मचारी होगा जो हिन्दी में काम करना चाहेगा ? वह लोग तो काम कम करना चाहते हैं । इसलिये इस काम को कौन चलायेगा जब उस से कहा जायेगा कि वह हिन्दी में भी काम करे और अंग्रेजी में भी अनुवाद तैयार करने का काम करे ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): I rise on a point of order. I do not want to object to what the hon. Member says; I am not opposed to whatever he says. What I want to say is this. He has raised a Constitutional point and he is entitled to speak only about the constitutionality of this measure. I do not want, in any way, to come in the way of his doing this. But after doing that, he is now speaking on the merits of the Bill, which is not correct.

MR. SPEAKER: I wanted to read cut the rule which Mr. Limaye quoted:

> "Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

It is only on that point. He cannot survey the merits of Hindi and all that.......... He cannot go into all those question now.

SHRI FRANK ANTHONY (Nominated—Anglo-Indians): The legislation is already on the Statute Book. How are we initiating a legislation? This is merely introducing a few consequential amendments.

MR. SPEAKER: Even if it is introducing an amendment, I can understand his speaking on the legality, but he should not go into the merits of the Bill now. He may speak only about the legality.

**श्री मधु लिमये** : नहीं, नहीं । ऐसा नहीं है । आप पहला हिस्सा पढ़िये । अगर संविधान की आपत्ति हो तो पूरी बहस कर सकते हैं । वैसे विरोध राजनीतिक कारणों से भी हो सकता है । मैं पढ़ता हूं :

> 'If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may, without further debate, put the question : . .

तो राजनीतिक कारणों से भी विरोध हो सकता है, और अगर संवैधानिक आपत्तियां हों तो स्पीकर साहब उस पर पूरी बहस की इजाजत दे सकते हैं ।. इसलिये मैं नियम के अनुसार बोल रहा हूं ।

SHRI MORARJI DESAI: That will be when the Bill is taken up. Just now it is only a Constitutional objection which is taken.

**श्री मधु लिमये** : आप नियम तो पढ़िये ।

**श्री मोरारजी देसाई** : मैं ने पढ़ा है ।

**श्री मधु लिमये** : कहां पढ़ा है ? अगर संवैधानिक आपत्ति नहीं तो भी इंट्रोडक्शन स्टेज पर विरोध हो सकता है । यह कई दफा हो चुका है ।

मैं निवेदन कर रहा था कि आज गैर-कांग्रेसी सरकारें जो बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं वे अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी को खत्म कर रही हैं और आइन्दा अंग्रेजी सूबों के लड़कों के ऊपर लादी नहीं जायेगी । मैं यह भी नहीं चाहता कि हिन्दी दक्षिण वालों पर लादी जाये । लेकिन अगर इस तरह का विधेयक आयेगा जिसमें किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं होगी तो रास्ता निकल सकता है, वना आप लोग विद्रोह के लिये आधार बना रहे हैं । इस लिये मैं प्रेम पूर्वक सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस विधेयक को वापस लें । किसी के ऊपर भी जबर्दस्ती न हो, न हिन्दी स्वीकारने वाले राज्यों पर अंग्रेजी की और न दूसरों पर हिन्दी की । इस तरह का कोई बीच का रास्ता निकालने के लिये अगर संवैधानिक संशोधन होता है तो उसका समर्थन करने के लिये हम तैयार हैं ।

SEVERAL HON. MEMBERS: *rose*—

MR. SPEAKER: I know, a large numbers want to speak, but I will allow only one from each Party; I do not want the whole House to speak on this now. Even those whom I permit may speak only on the legal and constitutional points and may not go into the merits of the Bill which can be done when we take up the Bill for discussion. Just now, it is only the legal aspect of it which can be discussed and it could be pointed out why this Bill should not be introduced. We can discuss whether this Bill is against the Constitution or against any law. These are the points which can be discussed. When the Bill comes up before the House again, naturally, hon. Members will have time to discuss the merits of the Bill; we shall naturally give more time then not only to the representatives of the parties but also to individual Members. Now, hon. Members could only point out constitutional and legal points and say how the Bill is against the Constitution and so on.

**श्री एस० एम० जोशी** (पूना) : अध्यक्ष महोदय, आप ने कहा कि चूंकि इस में कानून

[श्री एस० एम० जोशी]

की बात नहीं है इस लिये हम में से एक बोल सकता है। लेकिन में जानना चाहता हूं कि यह कानून जो बना है वह किस के लिये बना है, यह आ जाता है इसमें या नहीं? फिर अगर यह कानून के खिलाफ है तो वह भी तो बतलाना पड़ेगा।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : में एक बात की सफाई चाहता हूं कि यह प्वाइंट आफ आर्डर चल रहा या इंट्रोडक्शन का अपोजीशन हो रहा है ?

MR. SPEAKER : Now, it is only opposition to introduction.

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : अगर इंट्रोडक्शन का अपोजीशन है तो हमारा जो प्रोसीजर रहा है उस में मैं समझता हूं कि सिर्फ एक आदमी इंट्रोडक्शन को अपोज कर सकता है और मूवर कुछ कह सकता है। अगर आप प्रोसीजर वगैरह में जाते हैं तो हम को भी मोका मिलना चाहिये बोलने का। अगर इस पर बोलने के लिये आप सिर्फ पांच या दस आदमियों को बुलायेंगे और दूसरों को नहीं बुलायेंगे, तो यह नहीं हो सकता है।

MR. SPEAKER : I entirely agree. But they had written to me and taken my permission to oppose the introduction.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Even if so many people write, only one Member can speak, according to the rules. Supposing all of us write to you that we want to participate at the introduction stage and we want to oppose it, would you permit all of us ?

MR. SPEAKER : I do not know. Let us see the rule. I shall discuss it again. The procedure which the hon. Member suggests is very good and that normally should be the proper procedure namely that one Member should get up and speak opposing the introduction; others who want to oppose can certainly vote against it.

SHRI MORARJI DESAI : May I say that there are three stages? The first stage is that a constitutional objection is taken to the introduction of the Bill.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi): That is what is being done now.

SHRI MORARJI DESAI : If that is passed over, then the introduction of the Bill will be taken up, and on that Members can speak. If that is passed, then the consideration stage comes, and then hon. Members can speak on the Bill. Just now, however, it is only the constitutional point or point of order relating to the Constitution which can be raised. If at this stage, even the merits of the Bill are brought in, then the same thing will go on thrice. That is all that I would like to point out. I am not objecting to what is being said.

MR. SPEAKER : There is no contradiction in what both of them have said. Discussion on the merits cannot go on now. Of course, any Member may raise a constitutional point. There also, as Shri Surendranath Dwivedy says, if one Member opposes, that should be representative of everybody's opposition. After the introduction, when the discussion of the merits of the Bill comes up, a large number of Members can participate, nobody is preventing them or prohibiting them, and nobody is denying them of the chance. But now at the introduction stage, there is no provision in the rules for such a thing. The proviso to rule 72 says :

> "Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon.".

SHRI SONAVANE (Pandharpur) : May I submit that you have not allowed the motion to be moved yet ?

MR. SPEAKER : I am on my legs now. He should resume his seat. After I finish, I shall hear him.

SHRI SONAVANE : You should first allow the motion to be moved, and then you can permit this discussion.

MR. SPEAKER : I do not object to his getting up; but when I am speaking, he should sit down. After I finish, he can get up.

SHRI SONAVANE : You should allow the motion to be moved and then permit the discussion.

MR. SPEAKER : The hon. Member has every right to get up; I am not denying that; he is also an hon. Member of the House. But when I am on my legs, he should kindly sit down. It is not as though I am pointing this out only to Shri Sonavane : I am pointing out the same thing to the hon. Members on the other side of the House also that when I am on my legs, hon. Members should sit down. After I finish, he can get up.

I would like to have some light on this point from the Deputy Prime Minister also. The proviso says :

> "Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereof.".

This is the wording which raises a little confusion. It is not as though I had not looked into it earlier. I had looked into it earlier and it had been pointed out to me. The wording here is very categorical. If the opposition is on the ground that this Bill is outside the legislative competence of the House, then the Speaker may permit a full discussion thereon.

SHRI MORARJI DESAI : If you have permitted a full discussion, I have no objection, and I cannot raise any objection to it. But I think that permission has not yet been given, and, therefore, I do not think discussion at this stage is in order.

MR. SPEAKER : Because of the wording here, it is quite clear, that not only one Member should be allowed, as Shri Surendranath Dwivedy has said, but a full discussion could be permitted, but only on the legal aspect of it. Now, hon. Members, without going into the merits, namely whether the language must be Hindi or English or anything of that sort, may speak only on the constitutional and legal aspects.

Therefore, the Speaker may permit a full discussion thereon on the legal point. Normally, the procedure has been to allow only one Member to oppose. But here the rule is so clear. They wrote to me about this. When the rule is so clear, I wonder what the Speaker can do. I know this question of language is exciting people a little like religion. Therefore when I allow some friends to speak, it may be one or two or three on this side and one or two on the other side. But I would request all these who speak to strictly confine themselves to the legal and constitutional aspect. Later on, merits can be discussed when the Bill comes before the House.

Shri K. L. Gupta.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirapalli): On a point of order. The rule clearly says that if the Bill is outside the purview of the Constitution, then only the Speaker can allow at his discretion a full discussion. Here there is already a legislation called the Official Languages Act 1963. The present Bill is an amendment to that Act. Therefore, the question as to whether this Bill itself is beyond the constitutional competence of Parliament to discuss does not arise at all. Therefore, if there is opposition, a statement in opposition can be made only by one Member. It cannot be discussed further at this stage because the question of competence does not come at all. This is not a new legislation. It is a Bill which seeks to amend the Act already on the statute-book. So the ruling which you have given allowing an extended discussion will not be applicable to this particular case. Therefore, it is not in order to proceed as we are doing.

MR. SPEAKER : I have said that views can be expressed on the constitutional aspect before the Bill can be introduced. Let me hear what they have to say.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack): On a point of order. Kindly refer to the proviso to rule 72 which says that where a motion is opposed on the ground that

[Shri Srinibas Misra]

the Bill initiate legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon. What is the meaning of 'thereon'? 'Thereon' must refer to the Bill. And what is 'full discussion'? Full discussion must mean that everybody will discuss it. So it cannot be interpreted as meaning only a limited portion.

MR. SPEAKER: I have already explained it.

SHRI NAMBIAR: What is your ruling on my point of order?

MR. SPEAKER: I have said that I have permitted them to speak on the constitutional and legal aspect only at this stage. Later on, we shall have a full discussion on the merits of the Bill.

Shri K. L. Gupta. He must confine himself to the scope I have outlined. I will not allow a quarrel discussion.

**श्री कंवर लाल गुप्त** (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक काला विधेयक है और 98 प्रतिशत जनता जो भारतीय भाषायें बोलती है, उसके गले में अंग्रेज़ी को ज़बर्दस्ती ठूंसा जा रहा है। यह जो प्रयास है, यह संविधान...... (**इंटरप्शंस**)

**श्री मधु लिमये** : सब को मौका देंगे तो चिल्लाने की ज़रूरत क्या है ?

**श्री कंवर लाल गुप्त** : मैं समझता हूं कि यह एक प्रयास है जो कि आई० सी० एस० और आई० ए० एस० आफिसर्स के द्वारा किया जा रहा है जो कि जनता की भावनाओं को हमेशा के लिये कुचल कर रख देना चाहते ह। यह जो प्रयास है यह विधान के भी खिलाफ है। कैसे है यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इस बिल की धारा 5 इस प्रकार है :

> "The provisions of clause (a) of sub-section (1), and the provisions of sub-section (2), sub-section (3) and sub-section (4) shall remain in force until resolutions for the discontinuance of the use of the English language for the purposes mentioned therein have been passed by the Legislatures of all the States which have not adopted Hindi as their official language and until after considering the resolutions aforesaid, a resolution for such discontinuance has been passed by each House of Parliament."

इस धारा में स्पष्ट कहा गया है कि अगर एक भी अहिन्दी भाषी राज्य चाहेगा कि अंग्रेज़ी चलती रहे तो अंग्रेज़ी चलती रहेगी। दूसरी बात यह कही गई है कि अंग्रेज़ी तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे अहिन्दी भाषी राज्य चाहेंगे और तीसरी बात यह कही गई है कि जब तक राज्य सभा और लोक सभा दोनों अलग-अलग प्रस्ताव पास नहीं कर देंगी तब तक अंग्रेज़ी चलती रहेगी।

ये तीनों बातें विधान के खिलाफ हैं। पहली बात तो यह है कि वीटो पावर, वीटो का अधिकार एक स्टेट को दे देना गलत है, विधान के खिलाफ है और पार्लिमेंट के जो अधिकार हैं, जो अख्तयार हैं उन के ऊपर भी इससे पाबन्दी लगती है। पार्लिमेंट के सम्बन्ध के जो विषय हैं, जिस को यूनियन लिस्ट कहा जाता है उनके बारे में कानून आदि बनाने का सारा काम पार्लिमेन्ट को दिया गया है। उसके ऊपर इस धारा ने एक पाबन्दी लगा दी है और कह दिया है कि जब तक सारे राज्य यह नहीं कहेंगे तब तक अंग्रेज़ी चलती रहेगी। यह पाबन्दी कानून के खिलाफ है, विधान के खिलाफ है। मैं विधान का आर्टिकल 246 आपके सामने रखना चाहता हूं।

SHRI NAMBIAR: How did you allow the previous Act? The previous Act is there.

**श्री मधु लिमये** : उस वक्त नहीं किया होगा। हम थे नहीं उस वक्त, अब करना चाहते हैं।

**श्री कंवर लाल गुप्त :**

> "Notwithstanding anything in clauses (2) and (3), Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the "Union List")."

यह जो अधिकार है यह केवल पार्लिमेंट का है। इस धारा के ज़रिये इस पावर पर पाबन्दी लगती है कि जब तक एक भी गैर हिन्दी सरकार कहेगी कि अंग्रेज़ी रहनी चाहिये तो अंग्रेज़ी रहेगी। यह पाबन्दी विधान के खिलाफ है। मैं समझता हूं कि अगर पार्लिमेंट भी स्वयं यह कानून बनाये कि हम अपने अखत्यार के ऊपर पाबन्दी लगाते हैं तो वह भी गलत होगा।

पार्लिमेंट को जो विधान में नहीं है उसके खिलाफ जा कर रेस्ट्रिक्शन लगाने का, पाबन्दी लगाने का कोई अखत्यार नहीं है। इस विधान में केवल लोक सभा में एक या दो चीजों के ऊपर पाबन्दी लगाई गई है। आर्टिकल 368 में कहा गया है कि अगर कांस्टीट्यूशन में एमेंडमेंट करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। इसमें कहा गया है :

> "An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, it shall be presented to the President for his assent and upon such assent being given to the Bill, the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill :"

इस का मतलब यह है कि केवल संविधान में संशोधन करने के लिये ही सदन में दो-तिहाई मेजारिटी की ज़रूरत है और अन्य सब मामलों में यह सदन सिम्पल मेजारिटी से यानी एक वोट अधिक होने पर भी कानून बना सकता है या कोई संशोधन कर सकता है। लेकिन इस बिल में यह व्यवस्था कर दी गई है कि जब तक सब स्टेट्स इस बारे में प्रस्ताव पास न कर दें, तब तक अंग्रेज़ी को नहीं हटाया जा सकता है। इस लिये मेरा पहला एतराज़ यह है कि इस बारे में फैसला करने का अधिकार अहिन्दी भाषी स्टेट्स को देना संविधान के खिलाफ है।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम भारतीय भाषाओं के विरुद्ध नहीं हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय भाषायें बढ़ें और देश के सब कामों में उन का प्रयोग हो। एक भाषा के रूप में हम अंग्रेज़ी भाषा के भी खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम समझते हैं कि अंग्रेज़ी को देश की सर्व-साधारण जनता पर थोपना गलत है और यह राष्ट्र के हित के साथ खिलवाड़ है।

मेरा दूसरा एतराज़ यह है कि इस विधेयक के द्वारा देश के कुछ राज्यों के साथ भेद-भाव किया जा रहा है। पहले हमारे देश में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये तीन तरह की स्टेट्स थीं। उस के बाद संविधान में तबदीली कर के सब एक तरह की स्टेट्स बना दी गईं और कुछ यूनियन टेरीटेरीज़ बना दिये गये, जिन में दिल्ली भी शामिल है। इस बिल में अहिन्दी भाषी स्टेट्स को यह खास पावर दी गई है कि जब तक वे नहीं कहेंगी, तब तक अंग्रेज़ी को नहीं हटाया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में सब स्टेट्स को बराबर के अख्तयार दिये गये हैं, उस में ऐसा नहीं है कि हिन्दी-भाषी राज्यों और अहिन्दी भाषी राज्यों के अख्तयार भिन्न-भिन्न होंगे। चूंकि इस विधेयक के द्वारा कुछ राज्यों के साथ भेद-भाव किया जा रहा है, इसलिये यह संविधान के खिलाफ है।

हम इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि हिन्दी को किसी पर थोपा जाये। जो भाई हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं को नहीं पढ़ना चाहते हैं, जब तक उन की इच्छा न हो, वे

[श्री कंवर लाल गुप्त]

उन को न पढ़ें । लेकिन इस बिल के द्वारा इस देश के लोगों पर अंग्रेज़ी को ज़बरदस्ती लादा जा रहा है । मैं अपने डी० एम० के० के भाइयों को कहना चाहता हूं कि यदि वे मान लें कि हिन्दी और भारतीय भाषायें यहां की राष्ट्रीय भाषायें हैं, तो हम उन से बातचीत कर के कोई समझौता करने को तैयार हैं ।

इस बिल में कहा गया है कि अंग्रेज़ी को हटाने के लिये यह ज़रूरी होगा कि राज्य सभा और लोक सभा दोनों में इस बारे में प्रस्ताव पास करें, लेकिन यह बात संविधान के खिलाफ है । संविधान में कहा गया है कि अगर कोई पैसे का मामला आता है, तो लोक सभा जो कहेगी, वही ठीक होगा और राज्य सभा का उस से कोई ताल्लुक नहीं होगा । लेकिन अगर लोक सभा कोई दूसरा बिल पास कर के राज्य सभा को भेजती है और राज्य सभा उसको स्वीकार नहीं करती है, तो फिर दोनों हाउसिस का एक जाएंट सेशन होगा, जिस में इस बारे में निर्णय किया जायेगा । इस विधेयक ने संविधान की उस व्यवस्था को नहीं माना है और कहा है कि अंग्रेज़ी तब तक रहेगी, जब तक राज्य सभा और लोक सभा दोनों अलग से इस बारे में प्रस्ताव न पास कर दें । यह व्यवस्था संविधान के खिलाफ है । मान लीजिये, कल लोक सभा यह प्रस्ताव पास कर देती है कि अंग्रेज़ी जारी नहीं रहनी चाहिये, तो अंग्रेज़ी तब तक नहीं हटेगी, जब तक कि राज्य सभा भी प्रस्ताव पास न कर दे । संविधान में लोक सभा और राज्य सभा के जो सम्बन्ध निश्चित किये गये हैं, यह विधेयक उन के विरुद्ध जाता है ।

आखिर में मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम भारतीय भाषाओं के पक्ष में हैं । अगर हमारे डी० एम० के० के मित्र या दूसरे अहिन्दी-भाषी लोग यह स्वीकार कर लें कि वे अंग्रेज़ी को हटाने के लिये तैयार हैं, तो हम उन के साथ बैठ कर इस बारे में समझौता कर सकते हैं । कोई राज्य केन्द्र से अपना पत्र-व्यवहार तमिल या तेलगू में करें, इस में हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अंग्रेज़ी को ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है ।

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में दो आपत्तियां उठाई गई हैं : एक, यह कि बिल संविधान के प्रतिकूल है और दूसरा कि पार्लियामेंट को इस प्रकार का संशोधन करने का अख्तयार नहीं है । मैं समझता हूं कि ये दोनों आपत्तियां निराधार हैं । यह बात सही है कि संविधान की धारा 343 में यह व्यवस्था की गई थी कि इस देश में पन्द्रह वर्षों तक अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग होता रहेगा । उस से पहले हम ने यह माना था कि इस देश की राजकीय भाषा हिन्दी होगी । इस का साफ मन्तव्य, मन्शा यह था कि पन्द्रह वर्ष के बाद इस देश में राज-भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग होने लगेगा । लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी परिस्थितियां पैदा हुईं —जब हम इस बिल पर चर्चा करेंगे, तब हम उन सब बातों पर विचार करेंगे—कि देश में हिन्दी को जो सम्मान मिलना चाहिये था, जितने व्यापक पैमाने पर उस का प्रयोग होना चाहिये था और सब द्वारा उस को अपनाया जाना चाहिये था, वह सब कुछ नहीं हो पाया ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन विधेयक आज पेश हो रहा है, क्या वह संविधान के प्रतिकूल है ? मैं समझता हूं कि यह संविधान के अनुकूल है । संविधान के अनुच्छेद 343(3) में साफ कहा गया है :

> "Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years of (a) the English language,...."

अगर पन्द्रह वर्षों में देश में ऐसी परिस्थिति हो कि हम इस योग्य न हो पायें कि अंग्रेज़ी को बिलकुल हटा कर हिन्दी का प्रयोग करने लगें,

अगर पन्द्रह वर्षों के बाद पार्लियामेंट यह महसूस करे कि किसी भी कारण से अंग्रेज़ी का प्रयोग आगे भी करना ज़रूरी है, तो पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वह कानून के ज़रिये अंग्रेज़ी के प्रयोग की इजाज़त दे सकती है। यह बात बिलकुल स्पष्ट है। जिस अनुच्छेद की बुनियाद पर इस बिल का विरोध किया जा रहा है, उसी अनुच्छेद में इस की व्यवस्था की गई है।

पार्लियामेंट को यह अधिकार क्यों दिया गया है, यह बताने के लिये मैं आप का ध्यान अनुच्छेद 348 की तरफ दिलाना चाहता हूं। कुछ हिन्दी के समर्थक कहते हैं—मैं स्वयं भी उन में से एक हूं, जो समझते हैं कि हिन्दी हमारे देश की राजभाषा होनी चाहिये—कि पार्लियामेंट को इस बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 348(1)(ए) में साफ व्यवस्था की गई है :

> "Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides—
>
> (a) all proceedings in the Supreme Court and every High Court.... shall be in the English language.

संविधान में कहा गया है कि देश के हर उच्चतम न्यायालय और हर उच्च न्यायालय में अंग्रेज़ी का प्रयोग तब तक होता रहेगा, जब तक कि पार्लियामेंट कानून के ज़रिये इस बात की व्यवस्था न करे कि उनमें हिन्दी या दूसरी भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाये। यह बात हिन्दी के समर्थकों के खिलाफ जाती है। अगर पार्लियामेंट को संशोधन का यह अधिकार नहीं होगा, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अंग्रेज़ी का प्रयोग निरन्तर होता रहेगा।

संविधान में कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट ज़रूरी समझे, तो वह कानून ला कर हिन्दी या दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रयोग की व्यवस्था कर सकती है। हिन्दी के प्रति उनकी गहरी भावना के लिये मैं सेठ गोविन्द दास जी का बड़ा आदर करता हूं, लेकिन मैं उन की इस राय से सहमत नहीं हूं कि इस बिल को ला कर संविधान की अवहेलना की जा रही है। यह बिल संविधान के बिलकुल अनुरूप है जैसा कि श्री नम्बियार ने कहा है, तीन-चार साल पहले जो आफिशियल लैंग्वेज बिल हम इस सदन में पास कर चुके हैं, वह संविधान के अनुकूल है।

श्री मधु लिमये ने कहा है कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन को नहीं मानते, क्योंकि वह उनको नेता नहीं मानते। लेकिन इस देश का सौभाग्य रहा है कि राष्ट्र ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्र-नेता माना है। (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Order, order. That is not the point at issue. Shri Jawaharlal Nehru is no more with us. He has been an honoured leader. You may accept or you may not accept, that is not the point of discussion now. I do not think we should bring in his name and begin a discussion on that. That is not proper. May I request hon. Members not to mention his name now. This is a routine legislation that is before us and bringing in big names is not at all necessary.

**श्री मधु लिमये** : अध्यक्ष महोदय, माफ कीजियेगा, मैंने यह कहा था कि वह मेरे नेता नहीं थे। उस पर उनको क्या आपत्ति हो सकती है ? क्या मेरे नेता चुनने का भी उनको अधिकार है ?

**श्री चन्द्रजीत यादव** : तो मैंने भी कुछ नहीं कहा है। मैंने यह कहा है कि आप उनको नेता न मानते हों, लेकिन वह राष्ट्र के नेता रहे हैं......

MR. SPEAKER: Order, order. No more controversy about it.

**श्री चन्द्रजीत यादव** : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो बातें कही थीं कि संविधान में इस बात की व्यवस्था है। इस प्रकार का बिल ले आना संविधान के विपरीत नहीं है। बल्कि संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि संसद में इस प्रकार के बिल ला कर के उसमें संशोधन किये जा सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि गृह मंत्री ने जो बिल सदन के सामने पेश किया है वह विधान के विपरीत नहीं है। वह संविधान की व्यवस्था के अनुकूल है। इसलिये उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है।

SHRI PILOO MODY (Godhra): Mr. Speaker, Sir, as we have already seen, even at the introduction of this Bill that a great deal of heat has been generated in this House. Normally, a Bill on introduction is never opposed, yet this particular Bill has been opposed and a great many provisions of the Constitution and the rule books have been quoted back and forth. In judging the merits of the particular situation we have brought in a lot of law which, I may be forgiven for saying, most of us do not understand too well. If the question whether the Bill should or should not be introduced at this particular point is to be debated now, then it is quite obvious that the Bill will never go into the second stage where a full discussion on the merits or otherwise of it should take place.

I would like to urge everybody around here, let us sit down as human beings and discuss the merits of it. Whether it applies constitutionally or not can then be left to our eminent Law Minister who has the infinite capacity of twisting the law in any way that he chooses. Therefore, I would say that there is no need right now to discuss the constitutionality of the Bill, whether it is *ultra vires* or not. A Bill was already passed in 1963. It was not *ultra vires* then. This is an amending Bill. Whether the amendment is *ultra vires* of the Constitution, so that we cannot amend that Act and the Act has to remain as it is is, also a thing beyond the comprehension of most Members here.

Let us not mix up the constitutional issue with the issue of merit. Let us discuss the merit of it at the proper time. There is a great deal to be said on both sides. Let there be a free and frank exchange of views. Why are we all so hedged up that we want to snuff out any discussion, kill any thought on the subject. Therefore, I would urge the House and you, Sir, that the Bill may be introduced at this stage, the merits of it can be discussed at the second reading and the constitutional issues thrashed out later.

SHRI BAL RAJ MADHOK: I would like to submit...

MR. SPEAKER: Shri Kanwar Lal Gupta has already had his say.

SHRI NAMBIAR: We must be given an opportunity to express our viewpoint.

SHRI S. M. BANERJEE: (Kanpur): So also CPI.

MR. SPEAKER: Not on legal points.

SHRI MANOHARAN: As Shri Mody has rightly pointed out, if the consideration and discussion of this bill is allowed to go on unchecked like this, I am afraid this Bill will produce enough heat to spoil the whole issue. For the past so many years this issue has been engaging the attention of the country at large and in 1965 the Official Languages Bill was introduced by Shri Lal Bahadur Shastri and it was passed into an Act. The present Bill seeks to amend that Act, which was already passed. It is not a constitutional amendment. So, I cannot understand any validity or strength in the arguments advanced by hon. Members that it is against either the letter or the spirit of the Constitution. Whether it is to be introduced or not, it is left to the House to decide. But, so far as the DMK is concerned, nothing short of a constitutional amendment will satisfy the people of Tamilnad. I want to state that very categorically.

Government have now come forward with a Bill, which is trying to create an impression in the minds of the non-Hindi-speaking people that it is going to give statutory shape to the assurances given by the late Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru. Whether this Bill is trying to give, or gives, that impression, false or otherwise, it has to be decided later. But, so far as we are concerned, this Bill has been completely watered down and it will never satisfy us fully and completely.

MR. SPEAKER : That you can say later on during the consideration stage.

SHRI MANOHARAN : According to the Home Minister, this is a sort of compromise formula which may satisfy both the Hindi-speaking and non-Hindi-speaking areas. But I want to stress one point here. I still remember that some time back a great veteran of this country has expressed his anger and indignation by saying that the army should march to Madras State to protect Hindi and the people of India... (*Interruption*)

MR. SPEAKER : He is bringing in unnecessary things.

SHRI MANOHARAN : It is no other person than our venerable leader, Dr. Govind Das, I know that subsequently it has been contradicted.

DR. GOVIND DAS : I never said that.

SHRI MANOHARAN : Subsequently, it has been contradicted by him. It has become a regular practice for the Congress members to say something and contradict it subsequently, saying that he did not say so at all. So, that is not the point here.

My hon. friend, Shri Madhu Limaye, has referred to some constitutional provisions. I do not have any quarrel at all with him. Article 343 says very clearly that the official language of the Government of India is Hindi, and that too in Devanagari script. So far as this article is concerned, I want to say on behalf of the people of South—I think I can extend my horizon and speak on behalf of the people of Non-Hindi-speaking areas—that this article should be amended.

SHRI MANUBHAI PATEL (Dabhoi): That is only the view of Tamilnad, or perhaps that of DMK alone. That does not represent the view of the whole of South India. In any case, he does not represent our viewpoint.

SHRI MANOHARAN : I tell you that this article should be amended. So far as we are concerned, we will never accept the proposition that Hindi alone should be the official language of India.



13.00 HRS.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER : You can talk about legal points only. But I find that absolutely no legal point was raised; he was speaking on merits.

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai) : I will talk only on legal points. This Bill has been objected to on two constitutional points. Firstly, it is stated that it contravenes article 343. Now, article 343, clause (3) says :—

> "Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of—the English language, for such purposes as may be specified in the law."

It may be objected to that the particular purposes are not specified in the law, but may I point out that the whole includes the part? Therefore, when it is stated here that it can be used for all the official purposes of the Union, without exception, for all the official purposes for which the Hindi language is used the English language can be used as an associate language. Therefore it means that it is absolutely specific.

The second point which has been raised by my hon. friend from the Jana Sangh is that it also contravenes article 246. It is stated in article 246 :—

> "Notwithstanding anything in clauses (2) and (3), Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List I."

The competence of Parliament to make any law is not taken away by this Bill at all; on the other hand, Parliament itself is making this law. It is not somebody else who is making the law but it is the Parliament that is making the law. As to when exactly the particular provision that Hindi alone should be used as the exclusive language for official purposes, that time limit is laid down by Parliament and it is not laid down by anybody else. It is the Parliament that lays down that Hindi alone will be the official language of the State when all the States in the country accept it. Therefore it is within the competence of Parliament. It is not somebody

[Shri P. Ramamurti]

who comes and dictates to Parliament. It is within the competence of Parliament to lay down also the time when such-and-such a provision will come into force as per the constitutional provision itself. Therefore, I say that it is within the competence of Parliament.

**श्री स० मो० बनर्जी** : अध्यक्ष महोदय, काफी इस पर अभी बहस हो चुकी है । मैं यहां पर था नहीं इसलिये मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि इस चीज़ के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी अपनी नीति साफ कर चुकी है । हिन्दी भाषा के बारे में उन्होंने अपनी नीति का स्पष्टीकरण भी कर दिया कि हम लोग यह नहीं चाहते कि हिन्दी को जबरदस्ती किन्हीं लोगों पर लादा जाय या ऐसे लोगों के ऊपर अंग्रेज़ी लादी जाय जिनकी कि हिन्दी भाषा है ।

लेकिन जैसा आप ने अभी देखा इस बिल के लीव टू इंट्रोड्यूस मोशन पर कई वैधानिक प्वाइंट्स भी रेज़ किये गये हैं जिनका कि स्पष्टीकरण होना चाहिये । इस में कोई अवधि नहीं दी गई है और अगर कोई अवधि दी जाती इस बिल की तो मैं समझ सकता था लेकिन इस बिल को पढ़ने से मालूम होता है कि कोई अवधि उस की नहीं तो मेरा निवेदन आप से और प्रधान मंत्री जी से है कि इस बिल को आज जल्दबाज़ी में इंट्रोड्यूस न करें । इस पर कुछ समय लेकर और तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को बुला कर एक नेशनल कांशेसनेस जिस को कहते हैं वह ली जाये तब इस को इंट्रोड्यूस करना अच्छा होगा ।

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON) : Sir, nothing is left for me to answer after the clarification of the question of law by some of the hon. Members, particularly Shri Ramamurti, who very correctly interpreted the provision in article 343, clause (3). It is stated therein that even after 15 years Parliament has got the legal competence to lay down such purposes for which English may be continued to be used.

Now, the learned Member, Shri Gupta said that a right of veto to certain States is being given in this Bill. That again comes under the term "such purposes". For those purposes you can use the English language; that is to say, with respect to correspondence between the Centre and the non-Hindi-speaking States. That is one of the purposes. It is not giving a veto.

Regarding the use of English in the Centre, that also will come under "such purposes". "All the purposes" will also be included in the term "such purposes". We are, at this stage, concerned with legal competence. The Bill has been examined from that angle previously and I wish to submit that it is fully competent for Parliament to legislate.

MR. SPEAKER : Now, the question is that leave be granted to introduce a Bill to amend the Official Languages Act, 1963. Those in favour of the Bill being introduced may say 'Aye'.

SEVERAL HON. MEMBERS : 'Aye'.

MR. SPEAKER : Those against may say, 'No'.

SOME HON. MEMBERS : 'No'.

SHRI BAL RAJ MADHOK : I want to oppose it at the introduction stage.

MR. SPEAKER : You can vote against it.

SHRI BAL RAJ MADHOK : I want to oppose it; it has been the practice...

MR. SPEAKER : I have allowed enough.

SHRI BAL RAJ MADHOK : So far, they were speaking on the legal points. Now, we want to oppose it and we want to have an opportunity to explain...

MR. SPEAKER : Not at this stage.

SHRI BAL RAJ MADHOK : At this stage, we want to oppose it.

MR. SPEAKER : Please don't make a precedent which has never been in this House.

SHRI BAL RAJ MADHOK : The other day, when Mr. Ranga opposed the Bill....

MR. SPEAKER : About legal opinion, I have allowed it.

SHRI BAL RAJ MADHOK : When Mr. Ranga opposed the Bill, the other day...

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: What was clarified was the legal position. We were only discussing the legal issues. That discussion is now over. Now, we go to the introduction stage. If any Member has given notice to oppose it ...

MR. SPEAKER: He has not given any notice. Those who had given notice have been permitted already.

SHRI BAL RAJ MADHOK: That was only on legal points. You are trying to gag us ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: It is not a question of gagging. Your Party representative has already spoken.

SHRI BAL RAJ MADHOK: Only the legal objection was raised. Now, when the Bill is being introduced, I want to have an opportunity to explain ...

MR. SPEAKER. Kindly tell me the rule.

SHRI BAL RAJ MADHOK: This has been precedent.

MR. SPEAKER: No please. I would like to sit with Opposition Members and discuss it.

SHRI BAL RAJ MADHOK: When Mr. Ranga opposed it, it was not on legal points. You cannot have two rules.

MR. SPEAKER: Only legal points were expected.

SHRI BAL RAJ MADHOK: If you do not allow us, we will have to walk out.

MR. SPEAKER: If you want to walk out and I know your feelings for Hindi, that is a different thing. Tell me the rule.

**श्री यशपाल सिंह** (देहरादून) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने इसे अपोज करने के लिये नोटिस दिया हुआ है । इस लिये ऐसी बात नहीं है कि नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस मैंने दिया हुआ है ।

MR. SPEAKER: You were not in the House. You come one hour late and say this. Your name was called and you were not here.

**श्री कंवर लाल गुप्त:** अध्यक्ष महोदय, मैं रूल नं 72 कोट कर रहा हूं :

"If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion...."

आपने यह रूलिंग दी थी कि पहले इसके कांस्टोट्यूशनल ऐसपैक्ट पर बोला जाय....

SHRI MANUBHAI PATEL: On a point of order, Sir. You have already put the motion to vote. It is the process of voting. Nothing should be allowed now.

MR. SPEAKER: I have not yet declared the result. I agree with you.

**श्री कंवर लाल गुप्त:** अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट तो दीजिये । आप ने पहले जो रूलिंग दी थी जिसके कि तहत हम सब लोग बोले थे, उस में आप ने यह कहा था कि केवल इस का वैधानिक स्वरूप क्या है वह बतलाया जाये उस की मैरिट्स के ऊपर नहीं बोलना चाहिये । किसी ने भी उस की मैरिट पर नहीं बोला । एक-आध ने बोलने की कोशिश की भी तो उस को आप ने रोक दिया । अब यह जो ब्रीफ स्टेटमेंट इस के अन्दर है उस के तहत हर एक मेम्बर को अधिकार है कि इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर वह ब्रीफ स्टेटमेंट दे सकता है कि वह इस बिल के इंट्रोडक्शन को क्यों अपोज करना चाहता है ? रूल 72 में इस की व्यवस्था मौजूद है और इस लिये कृपा कर के श्री बलराज मधोक को जो कि इस का इंट्रोडक्शन अपोज करना चाहते हैं उन को बोलने की अनुमति दीजिये ।

MR. SPEAKER: Not at this stage. It is very clear. If you want to change the rule, I have no objection. You can oppose it. Now, I put it to vote.

I will now put it to the vote of the House.

The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Official Languages Act, 1963."

*The Lok Sabha divided.*

DIVISION No. 6] AYES [13-15 HRS.

Abraham, Shri K. M.
Aga, Shri Ahmad
Ahmed, Shri F. A.
Amat, Shri D.
Amin, Shri Ramchandra J.
Anirudhan, Shri K.
Ankineedu, Shri
Azad, Shri Bhagwat Jha
Bajpai, Shri Shashibhushan
Bajpai, Shri Vidya Dhar
Barrow, Shri
Basu, Dr. Maitreyee
Bhagat, Shri B. R.
Bhagavati, Shri
Bhanu Prakash Singh, Shri
Brahma, Shri Rupnath
Buta Singh, Shri
Chakrapani, Shri C. K.
Chanda, Shri Anil K.
Chandra Shekhar Singh, Shri
Chatterjee, Shri N. C.
Chaturvedi, Shri R. L.
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Chaudhuri, Shri Tridib Kumar
Chavan, Shri D. R.
Chavan, Shri Y. B.
Das, Shri N. T.
Dass, Shri C.
Deiveekan, Shri
Deo, Shri K. P. Singh
Desai, Shri Morarji
Deshmukh, Shri K. G.
Dhandapani, Shri
Dhrangadhra, Shri Sriraj Meghrajje
Dinesh Singh, Shri
Dipa, Shri A.
Dixit, Shri G. C.
Dwivedi, Shri Nageshwar
Gandhi, Shrimati Indira
Ganesh, Shri K. R.
Ganga Devi, Shrimati
Gavit, Shri Tukaram
Ghosh, Shri Parimal
Gopalan, Shri P.
Gowd, Shri Gadilingana
Gowder, Shri Nanja
Guha, Shri Samar
Gupta, Shri Indrajit
Gupta, Shri Lakhan Lal
Gupta, Shri Ram Kishan
Haldar, Shri K.
Hari Krishna, Shri
Iqbal Singh, Shri
Jadhav, Shri V. N.
Jagjiwan Ram, Shri
Jamir, Shri S. C.
Jha, Shri Bhogendra
Kamala Kumari, Shrimati
Kandappan, Shri S.
Kasture, Shri A. S.
Kedaria, Shri C. M.
Khan, Shri H. Ajmal
Khan, Shri Latafat Ali
Khanna, Shri P. K.
Kiruttinan, Shri
Kisku, Shri A. K.
Kotoki, Shri Liladhar
Koushik, Shri K. M.
Krishna, Shri M. R.
Krishnamoorthi, Shri V.
Kureel, Shri B. N.
Kushok Bakula, Shri
Lalit Sen, Shri
Laskar, Shri N. R.
Lobo Prabhu, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Maharaja Singh, Shri
Mahida, Shri Narendra Singh
Mandal, Dr. P.
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Mane, Shri Shankarrao.
Mangalathumadam, Shri
Monoharan, Shri
Maran, Shri Murasoli
Meghachandra, Shri M.
Mehta, Shri Asoka
Mehta, Shri P. M.
Menon, Shri Govinda
Menon, Shri Vishwanatha
Mirza, Shri Bakar Ali
Mody, Shri Piloo
Mohamed Imam, Shri J.
Mohammad Ismail, Shri
Mukerjee, Shri H. N.
Mukerjee, Shrimati Sharda
Murthy, Shri B. S.
Murti, Shri M. S.
Muthusami, Shri C.
Nahata, Shri Amrit
Naidu, Shri Chengalraya
Naik, Shri G. C.
Naik, Shri R. V.
Nambiar, Shri

Pandey, Shri K. N.
Pandey, Shri Sarjoo
Pant, Shri K. C.
Parmar, Shri Bhaljibhai
Partap Singh, Shri
Patel, Shri Manubhai
Patil Shri Anrutrao
Patil, Shri Deorao
Patil, Shri N. R.
Patil, Shri S. B.
Poonacha, Shri C. M.
Qureshi, Shri Shaffi
Radhabai, Shrimati B.
Raj Deo Singh, Shri
Rajani Gandha, Kumari
Rajaram, Shri
Ram Dhan, Shri
Ram Dhani Das, Shri
Ram Kishan, Shri
Ram Subhag Singh, Dr.
Ramabadran, Shri T. D.
Ramamoorthy, Shri S. P.
Ramamurti, Shri P.
Ramani, Shri K.
Ramshekhar Prasad Singh, Shri
Randhir Singh, Shri
Rane, Shri
Rao, Shri Jagannath
Rao, Shri Rameshwar
Rao, Shri V. Narasimha
Raut, Shri Bhola
Reddi, Shri G. S.
Reddy, Shri R. D.
Reddy, Shri Surendar
Roy, Shri Bishwanath
Sadhu Ram, Shri
Saleem, Shri M. Y.
Sambasivam, Shri
Sambhali, Shri Ishaq
Sanghi, Shri N. K.
Sankata Prasad, Dr.
Sapre, Shrimati Tara
Satya Narain Singh, Shri
Sayyad Ali, Shri
Sen, Shri A. K.
Sen, Shri Dwaipayan
Sequeria, Shri
Sethi, Shri P. C.
Sezhiyan, Shri
Shah, Shri T. P.
Shambhu Nath, Shri
Sharma, Shri M. R.
Shastri, Shri Sheopujan
Sher Singh, Shri
Sheth, Shri T. M.
Shinde, Shri Annasahib
Shiv Chandika Prasad, Shri
Shivappa, Shri N.
Shukla, Shri S. N.
Shukla, Shri Vidya Charan
Singh, Shri D. N.
Sinha, Shri Satya Narayan
Snatak, Shri Nar Deo
Somasundaram, Shri S. D.
Sonavane, Shri
Supakar, Shri Sradhakar
Surendra Pal Singh, Shri
Sursingh, Shri
Suryanarayana, Shri K.
Swaran Singh, Shri
Tiwary, Shri K. N.
Tripathi, Shri K. D.
Virbhadra Singh, Shri
Viswambharan, Shri P.
Viswanatham, Shri Tenneti
Xavier, Shri S.
Yadav, Shri Chandra Jeet
Yajnik, Shri

## NOES

Bharat Singh, Shri
Brij Bhushan Lal, Shri
Devgun, Shri Hardayal
Digvijai Nath, Shri
Govind Das, Dr.
Gupta, Shri Kanwar Lal
Jha, Shri S. C.
Joshi, Shri Jagannath Rao
Joshi, Shri S. M.
Kachwai, Shri Hukam Chand
Kameshwar Singh, Shri
Kothari, Shri S. S.
Limaye, Shri Madhu
Madhok, Shri Bal Raj
Molahu Prasad, Shri
Onkar Singh, Shri
Patel, Shri J. H.
Ranjit Singh, Shri
Saboo, Shri Shri Gopal
Sharma, Shri N. S.
Shastri, Shri Raghuvir Singh
Shinkre, Shri
Sondhi, Shri M. L.
Suraj Bhan, Shri
Yashpal Singh, Shri

SOME HON. MEMBERS : The Prime Minister has voted against !

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : It was by mistake. It may please be corrected as 'for'.

MR. SPEAKER : By mistake she has pressed the wrong button. Now she wants it to be corrected.

**श्री कंवर लाल गुप्त** : बोर्ड पर जो इंडिकेशन है उस में करेक्शन कैसे हो सकता है ? हां, अगर प्रधान मंत्री कह रही हैं कि वह हिन्दी के खिलाफ हैं, तो ठीक है ।

MR. SPEAKER : We have permitted that in the past.

**श्रीमती इंदिरा गांधी** : मैं हिन्दी के खिलाफ नहीं हूं ।

MR. SPEAKER : The result of the Division is : Ayes—181; Noes—25.

*The motion was adopted.*

SHRI Y. B. CHAVAN : Sir, I introduce the Bill.

13.17 HRS.

*The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.*

---

*The Lok Sabha re-assembled after lunch at seven minutes past Fourteen of the Clock.*

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

## RE : QUORUM IN THE HOUSE

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I have a submission to make. You know that it took about ten minutes to have quorum in this House just now. We decided in the Whips' Conference that it is the primary responsibility of the ruling party to have quorum in the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Could he not communicate with the concerned Minister ?

SHRI S. M. BANERJEE : It applies to you. My party people came here at 2 P.M. We are not going to get more than Rs. 31 for this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not fair. The House adjourned a bit late. They wanted time for lunch. That must be taken into consideration.

SHRI S. M. BANERJEE : You should have fixed 2.20 then. I could not have a grub.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : You could fix it even at 4.20.

14.09 HRS.

## COURT FEES (DELHI AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : I beg to move :

> "That the Bill further to amend the Court-fees Act, 1870, as in force in the Union Territory of Delhi, be taken into consideration".

This is a short Bill which seeks to amend the Court-fees Act of 1870. The House will remember that a few months back we enacted a legislation to provide for a High Court for the Union Territory of Delhi. When this High Court for the Delhi Union Territory was constituted, we transferred the ordinary original civil jurisdiction for civil suits of the value exceeding Rs. 25,000 to it. Before this provision was made, suits of this amount were presented in the District Court and regular court fee was charged.

Section 4 of the Court Fee Act contains a provision for charging fees in matters coming up before the High Court, but after some time a question was raised whether that court fee could be levied under that section in suits which are filed in the High Court in view of ordinary original civil jurisdiction. After the point was examined, it was found that no court fees could be levied by the High Court under that section.

As would be apparent, it was not the intention of the Government that no court fee should be charged on suits of the value exceeding Rs. 25,000, but this came about because of the lacuna in the Delhi High Court Act which was passed by this hon. House. A draft Bill to correct this lacuna was taken up. It was sent to the Metropolitan Council and it processed the Bill, and when it came to us it was a little late and we could not put it up before Parliament because of very heavy backlog of legislative business that was pending here, and we had to issue an ordinance to see